नवसर्जन संस्कृति

TITLE CODE : UPHIN51496
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 227
दि. 18.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

यूपी के आत्मविश्वास का कारण कानून का राज, प्रदेश की छवि बदली : सीएम

लखनऊ (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पीएसी के स्थापना दिवस के अवसर पर पीएसी जवानों को संबोधित किया और बीते साढ़े आठ साल में पीएसी को और बेहतर बनाने के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 78 वर्ष से पीएसी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग व समर्पण का रहा है। उन्होंने जवानों से अपील की कि साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिक दक्षता व कठिन प्रशिक्षण ही आपकी पहचान बननी चाहिए। सरकार आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान व सरकार के स्तर पर मिलने वाली सुविधा-संसाधन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यूपी के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी दे सकता है। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएसी के स्थापना दिवस समारोह-2025 का शुभारंभ किया। सीएम ने पीएसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। सीएम ने 78वर्ष के गौरवशाली इतिहास के लिए पीएसी बल को बधाई दी।

संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है पीएसी बल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पीएसी बल आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, प्रदेश में महत्वपूर्ण त्योहारों, अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन, लोकतंत्र के महापर्व ह्यचुनावह्न को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है। पीएसी के अधिकारी व कार्मिक विभिन्न आयामों के माध्यम से न सिर्फ यूपी, बल्कि देश के अंदर यूपी पीएसी बल, एसएसएफ, यातायात पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक ड्यूटी, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक, एटीएस व एसटीएफ कमांडो के रूप में सेवाएं प्रदान कर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

सीएम योगी ने पीएसी के अदम्य साहस को भी गिनाया

सीएम योगी ने पीएसी बल के अदम्य साहस की चर्चा की। बताया कि 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले का जवाब दिया और पांचों आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 में श्रीराम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में

आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी आतंकियों को मार गिराया गया था।

यूपी की बेहतर छवि को देश के सामने रखने मे मिली सफलता

सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पीएसी की 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए यूपी के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखा और आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से यूपी की बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की। संख्या, क्षमता, प्रशिक्षण, तकनीक के स्तर पर पीएसी की सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। अत्याधुनिक हथियारों व दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित करते हुए पीएसी को एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टीसेल लांचर, एंटी राइड गन, टियर गैस गन समेत अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी प्रदान किए गए।

हमारी सरकार ने पीएसी में 41,893 आरक्षियों व 698 प्लाटून कमांडर की भर्ती की

सीएम योगी ने कहा कि पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए पूर्व में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम को अपडेट करते हुए एबीसी आदि ग्रेड सुनिश्चित कर उन्हें बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पीएसी में 41,893 आरक्षियों व 698 प्लाटून कमांडर की भर्ती की। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडर के पद पर 1648 तथा आरक्षी के पद पर 15131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। शीघ्र ही यह भर्ती भी संपन्न होगी।

सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी व 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर सेवायोजन प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर पर 7 अभ्यर्थियों के सेवायोजन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3772 उपनिरीक्षकों के पदों में वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4042 मुख्य आरक्षी तथा 13313 आरक्षियों को पदोन्नति दी गई। 352 मुख्य आरक्षी, 1015 आरक्षियों की पदोन्नति कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है।

खेल के बजट को 70 लाख से बढ़ाकर किया गया 10 करोड़ रुपये

सीएम योगी ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए यूपी में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की छह कंपनियों में 18 टीमें प्रदेश को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस को बढ़ावा देने के लिए दो प्रतिशत पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हमारी सरकार द्वारा संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अधियाचन व भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से भेंट की

गांधीनगर, 17 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को अहमदाबाद स्थित मजार-ए-कुत्बी में दाऊदी बोहरा समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट दाऊदी बोहरा समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु के अहमदाबाद के वार्षिक दौरे के दौरान हुई।

इस मुलाकात के दौरान सैयदना साहब ने जनकल्याण, सामाजिक समरसता और जिम्मेदार नागरिकता के महत्व पर चर्चा की।

उन्होंने अहमदाबाद के निरंतर हो रहे विकास और शहर की स्थिरता, व्यवस्था एवं नागरिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व की प्रशंसा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 32वें दाई सैयदना कुतबखान कुतुबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी दरगाह पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहर में इस समाज के इतिहास और विरासत की सराहना की।

संक्षिप्त समाचार

पीएम मोदी जी अपनी तीन देशों की विदेश यात्रा के तीसरे और अंतिम पड़ाव पर ओमान पहुंचे

नई दिल्ली. भारत और ओमान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को मस्कट में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा पर हैं. मोदी मंगलवार को जॉर्डन से इथियोपिया पहुंचे और अदीस अबाबा से ओमान के लिए रवाना होंगे. अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मस्कट पहुंच चुके हैं.

भारत और अर्जेंटीना ने द्विपक्षीय कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विनिमय को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर-आईएनटीए कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए

● नई कार्य योजना के माध्यम से संवहनीय कृषि विज्ञान, डिजिटल कृषि और जैव प्रौद्योगिकी में भारत-अर्जेंटीना सहयोग को सशक्त बनाया जा रहा है

● आईसीएआर-आईएनटीए सहयोग के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, पशुधन सुधार और फसल जैव प्रौद्योगिकी पर संयुक्त रूप से ध्यान केंद्रित किया गया

इस कार्य योजना में जर्मप्लाज्म विनिमय, विशेषज्ञों की सहभागिता और अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण शामिल

● आईसीएआर-आईएनटीए समझौते के तहत भारत और अर्जेंटीना ने तिलहन, दलहन, मशीनीकरण और पादप एवं पशु स्वास्थ्य पर अपनी साझेदारी बढ़ाई

(जीएनएस)।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अर्जेंटीना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ने कृषि अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी विनिमय में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना 2025-2027 पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव

और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट तथा भारत में अर्जेंटीना गणराज्य के राजदूत मारियानो ऑगस्टिन कौसिनो ने आज आईसीएआर-आईएनटीए कार्य योजना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता द्विपक्षीय कृषि सहयोग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस कार्य योजना में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बिना जुताई के खेती, संवहनीय कृषि विज्ञान, मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और पानी में उर्वरक मिलाकर सिंचाई, फसल एवं पशु जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन वृद्धि, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय फसलों के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकियों, डिजिटल कृषि, जैव सुरक्षा और पादप स्वच्छता के उपायों और मूल्य श्रृंखला विकास के क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति हुई।

नियोजित अध्ययन दौरे और प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रीनहाउस सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती और समशीतोष्ण फल, कटाई के बाद फलों/सब्जियों का संरक्षण, अधिक पोषण वाले खाद्य पदार्थों का विकास, पशु चिकित्सा निदान, पशुपालन, अपशिष्ट-से-संसाधन में परिवर्तन की प्रौद्योगिकी, सूक्ष्मजीवों से संबंधित (माइक्रोबियल) फीड वृद्धि, डिजिटल कृषि और स्वच्छता और पादप स्वास्थ्य जैसे विषयों को शामिल किया गया है। जर्मप्लाज्म आदान प्रदान में सोयाबीन, सूरजमुखी, मक्का, ब्लूबेरी, साइट्रस फल, जंगली पपीता, अमरूद की प्रजातियां और चुनिंदा सब्जियों शामिल होंगी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली और सोनीपत की वायु प्रदूषण शमन कार्य योजनाओं पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

यह दिल्ली-एनसीआर के लिए समीक्षा बैठकों की श्रृंखला में तीसरी बैठक थी।

श्री भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और लागू करने योग्य समाधान विकसित करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने और आम जनता को असुविधा पहुंचाने के बजाय प्रमुख प्रदूषकों को लक्षित करने का आ'ान किया

उन्होंने दिल्ली में अतिक्रमण हटाने, पुराने कचरा डंप स्थलों को समाप्त करने, अंतिम छोर तक सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने और व्यस्त समय के दौरान सिग्नल-मुक्त आवाजाही के लिए सड़क गलियारों की पहचान करने को भी आवश्यक बताया

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने ह्यफ्रॉम एक्शन टू इम्पैक्टह्न नामक कार्यक्रम को संबोधित किया

यह कार्यक्रम 'एआई इम्पैक्ट समिट' के औपचारिक कर्टेन रेजर के

रूप में आयोजित किया गया थाए यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया

(जीएनएस)।

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद ने 16 दिसंबर, 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में "फ्रॉम एक्शन टू इम्पैक्ट" नामक कार्यक्रम को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने देश के अदम्य वीरों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का स्वागत किया

परमवीर दीर्घा गुलामी की मानसिकता से निकलकर नव-जागृत राष्ट्रीय चेतना की ओर भारत की यात्रा को दशार्ती है: प्रधानमंत्री

परमवीर दीर्घा युवाओं को भारत की शौर्य परंपरा और राष्ट्रीय संकल्प से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का स्वागत किया और कहा कि वहाँ प्रदर्शित चित्र देश के अदम्य वीरों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि और उनके बलिदानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि ये चित्र उन वीर योद्धाओं का सम्मान करते हैं,जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से मातृभूमि की रक्षा की और भारत की

एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के परमवीरों की इस दीर्घा को, दो परमवीर चक्र विजेताओं और अन्य विजेताओं के परिवारजनों की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्र को अर्पित किया जाना और भी विशेष है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लंबे कालखंड तक राष्ट्रपति भवन की गैलरी में ब्रिटिश काल के सैनिकों के चित्र लगे थे।

52,400 आगंतुकों के साथ खिजड़िया ने मजबूत की गुजरात की इको-टूरिज्म पहचान

■ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में गुजरात की इकोलॉजिकल उत्कृष्टता के बेजोड़ उदाहरण के रूप में उभरेगा खिजड़िया पक्षी अभयारण्य

■ रामसर साइट के दर्जे के साथ खिजड़िया अभयारण्य गुजरात के टिकाऊ विकास का जीवंत उदाहरण

गांधीनगर, 17 दिसंबर : खिजड़िया पक्षी अभयारण्य ने वर्ष 2024-25 के दौरान 52,400 से अधिक सैलानियों को आकर्षित कर इको-टूरिज्म क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान को मजबूत किया है। राज्य में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तब यह अभयारण्य पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) उत्कृष्टता और टिकाऊ विकास के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बन रहा है।

वीजीआरसी 2026 से पहले, जामनगर के निकट स्थित खिजड़िया रामसर स्थल गुजरात के महत्वपूर्ण पाकृतिक लैंडमार्क के रूप में उभरकर सामने आया है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र आज राज्य के अग्रणी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, जहां प्राकृतिक लैंडस्केप, वन्यजीवन, तटीय सुंदरता, आध्यात्मिक स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनोखा

संगम देखने को मिलता है। सफेद रण से लेकर सौराष्ट्र के तीर्थ स्थलों, समुद्र तट और अभयारण्यों तक की यात्रा पर्यटकों को विविधतापूर्ण और यादगार अनुभव देती है।

600 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला खिजड़िया पक्षी अभयारण्य मीठे और खारे पानी के दुर्लभ संगम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह अनोखा पारिस्थितिक तंत्र पक्षियों के लिए एक विविधतापूर्ण निवास उपलब्ध कराता है। गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान यहां 317 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई थी, जो 2024-25 में बढ़कर 332 हो गई है, जो इस अभयारण्य की लगातार विकसित होती जैव विविधता का प्रमाण है।

इस पारिस्थितिक समृद्धि को 2022 में वैश्विक मान्यता मिली, जब खिजड़िया को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। राज्य सरकार यहां पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रही है, जिसमें वॉच टावर, वन-कुटीर, पक्षी निरीक्षण प्लेटफॉर्म, इंटरप्रिटेशन सेंटर, सेल्फी पॉइंट और जानकारी देने वाले साइन बोर्ड शामिल हैं।

अभयारण्य की मुख्य ताकत इसके विविधतापूर्ण और सुरक्षित आवास स्थल में है, जहां मीठे पानी का बहाव समुद्री ज्वार के साथ मिलता है, और तटबंधों एवं खंदकों के नेटवर्क से यह और भी समृद्ध हो जाता है, जो वन्यजीवों के लिए आदर्श माइक्रोहैबिटेट यानी सूक्ष्म आवास बनाते हैं। ये सुविधाएं खिजड़िया को भारत के सबसे जीवंत पक्षी स्थलों में से एक बनाती हैं। साथ ही, यह आर्द्रभूमि (वेटलैंड) संरक्षण के प्रति गुजरात के वैज्ञानिक और योजनाबद्ध दृष्टिकोण को भी मजबूत बनाती है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जियो पारसी योजना की पारसी समुदाय ने व्यासपक सराहना की

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक पारसी समुदाय (जोरोस्ट्रियन) की आबादी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1941 में 1,14,000 से घटकर वर्ष 2011 में 57,264 रह गई है। पारसी समुदाय की घटती संख्या को रोकने के लिए सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2013-14 में जियो पारसी योजना शुरू की थी। इस योजना के तीन घटक हैं:

i) चिकित्सा सहायता झ बांझपन, गर्भावस्था और नवजात शिशु संबंधी जटिलताओं के उपचार के लिए पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह सहायता 30 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है।

ii) समुदाय स्वास्थ्य - पारसी

दंपतियों को बच्चों और आश्रित सदस्यों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह सहायता उन पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 15 लाख रुपये तक है।

iii) प्रचार-प्रसार - योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

इस योजना के तहत सहायता राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अन्य सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को जारी की जा रही है।

पिछले 5 वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2024-25) के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 17.64 करोड़ रुपये का व्यय हुआ और 232 शिशुओं का जन्म हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) ने वर्ष 2025 के दौरान इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया था। आईआईपीएस की रिपोर्ट के अनुसार यह योजना लक्षित जनसंख्या तक पहुंचने में काफी हद तक सफल रही है और पारसी समुदाय ने इस योजना की उपयोगिता के बारे में लगभग सर्वसम्मत स्वीकृति दी थी।

इस योजना को वित्त आयोग के अगले सत्र के दौरान जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

वामपंथी उग्रवाद: राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी

(जीएनएस)।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सरकारों के अधीन हैं। हालांकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" को मंजूरी दी गई थी। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और अधिकारों को सुनिश्चित करने आदि सहित बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और इसका भौगोलिक प्रसार सीमित हुआ है। वामपंथी उग्रवाद, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के समय में काफी हद तक कम हो गया है और अब केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया है।

नक्सलवादी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) द्वारा की गई हिंसा की घटनाएं 2010 में 1936 के उच्च स्तर से घटकर 2025 में 222 रह गईं, जो 89% की गिरावट है। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतें भी 2010 में 1005 के उच्च स्तर से घटकर 2025 में 95 रह गईं, जो 91% की गिरावट है। नक्सलवादी उग्रवादियो प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70, अप्रैल 2024 में 38, अप्रैल 2025 में 18 और अक्टूबर 2025 में केवल 11 रह गई है। अब केवल 3 जिले ही सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की श्रेणी में आते हैं। सरकार द्वारा आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से नक्सलवाद के मूल कारण का समाधान हुआ है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति, साथ ही बुनियादी ढांचे में निवेश ने सार्वजनिक/निजी निवेश में वृद्धि सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है।

सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) बटालियन, हेलीकॉप्टर सहायता, शिविर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करना, किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण और भारतीय रिजर्व बटालियनों को मंजूरी देना आदि प्रदान करती है।

राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सुरक्षा बलों के परिचालन व्यय और प्रशिक्षण आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी कार्यकर्ताओं के पुनर्वास, उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों और शहीद सुरक्षा बल कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत उग्रवादी हिंसा से प्रभावित राज्यों को लगभग 1,643 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (एसआईबी), जिला पुलिस को मजबूत करने और किलेबंद पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण के लिए उग्रवादी हिंसा से प्रभावित राज्यों को 1757 करोड़ रुपये के कार्यों की मंजूरी दी गई है।

वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार और राज्य सरकारों ने व्यापक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियां तैयार की हैं। भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास' नीति के माध्यम से राज्यों को इस प्रयास में सहयोग प्रदान करती है। भारत सरकार एसआरई योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवादियों से प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के अलावा, उच्च श्रेणी के वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) के कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य एलडब्ल्यूई कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत हथियार और गोला-बारूद आत्मसमर्पण करने पर प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। साथ ही, तीन वर्षों के लिए 10,000 रुपये के मासिक वजीफे के साथ उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है। प्रभावित राज्यों ने अपनी आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियों को आकर्षक और समकालीन बनाने के लिए उनमें संशोधन किया हैं।

राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस आधुनिकीकरण हेतु सहायता" योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को हथियारों, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों के निर्माण, गतिशीलता, पुलिस आवास और अन्य पुलिस अवसंरचना आदि के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहायता प्रदान की जाती है।

वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) की वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने और सी पी आई (माओवादी) तथा उसके वित्तीय समर्थकों के बीच सांठगांठ का पदार्फाश करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एलडब्ल्यूई को मिलने वाले धन और अन्य संसाधनों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए, राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न माध्यमों से समन्वित कार्रवाई कर रही है।

भारत सरकार का सुरक्षा अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण रहा है। पिछले दशक में 656 किलेबंद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा, पिछले छह वर्षों में नक्सलवादी उग्रवादियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में 377 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं।

विकास के मोर्चे पर, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए कई विशिष्ट पहलें की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू हुए इनमें से कुछ कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है :

ड्ड सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) और सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) नामक 2 एलडब्ल्यूई विशिष्ट योजनाओं के तहत 8301 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है।

ड्ड बिजली संकट से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 6,775 टावर चालू किए गए हैं।

ड्ड कौशल विकास के लिए 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 5 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) कार्यरत हैं।

ड्ड आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 95 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए हैं।

ड्ड वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं से लैस 4,262 डाकघर खोले हैं। अधिकांश एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 719 बैंक शाखाएं और 204 एटीएम खोले गए हैं।

ड्ड विकास को और गति देने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत अधिकांश एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना की महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कुल लगभग 1,576 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

वर्ष 2020-2025 की अवधि के दौरान देश में नागरिकों की मृत्यु और सुरक्षा बलों के शहीदों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

भारत सरकार अपने देश से वामपंथी उग्रवाद के पूर्ण उन्मूलन और वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यापक सांस्कृतिक प्रसार और राजस्व सृजन के लिए प्रसार भारती ने कंटेंट सिंडिकेशन फ्रेमवर्क की शुरूआत की

(जीएनएस)।

प्रसार भारती ने सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार और सामग्री के मुद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने सार्वजनिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए सामग्री सिंडिकेशन नीति, 2025 का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रसार भारती की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

मीडिया जगत के प्रमुख हितधारकों के साथ एक सुनियोजित उद्योग परामर्श आयोजित किया गया। इनमें ओटीटी प्लेटफॉर्म, लीनियर टीवी प्रसारक, रेडियो नेटवर्क, दूरसंचार कंपनियां, आईपीटीवी ऑपरेटर और कंटेंट एग्रीगेटर शामिल हैं।

इस नीति का उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित सामग्री, संग्रहित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सामग्री, और लाइव कवरेज (सरकारी कार्यक्रम, त्योहार, खेल आदि) से आय अर्जित करना है। इसमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित डिजिटल-फर्स्ट सामग्री को भी ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा मसौदा नीति में प्रसार भारती के स्वामित्व वाली कमीशन प्राप्त, सह-निर्मित, लाइसेंस प्राप्त और अन्य सामग्री के मुद्रीकरण का प्रस्ताव है। कंटेंट सिंडिकेशन नीति के मसौदे में प्रसार भारती की सामग्री की पहुंच का विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

इसमें लचीले लाइसेंसिंग मॉडल जैसे कि फ्लैट शुल्क, राजस्व साझाकरण, राजस्व साझाकरण के साथ न्यूनतम गारंटी आदि का प्रावधान है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में श्री सेल्वगनापति टीएम द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उपलब्ध कराई।

ओटीटी क्षेत्र, भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक सांस्कृतिक पहुंच के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहा है

वीडियो सदस्यता (सब्सक्रिप्शन) से होने वाली आय 2024 में 11% बढ़कर 9,200 करोड़ रुपये तक पहुंची

प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के शुरू होने के पहले वर्ष में ही 80 लाख उपयोगकर्ता हुए

(जीएनएस)।

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) क्षेत्र ने भारतीय कहानियों, रचनात्मक प्रतिभा, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्र फिल्म निर्माण तक वैश्विक पहुंच को सक्षम बनाकर भारत की सॉफ्ट पावर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उद्योग जगत के अनुमानों (एफ आई सी सी आई-ईवाई मीडिया और मनोरंजन उद्योग रिपोर्ट 2025) के अनुसार, वीडियो सब्सक्रिप्शन से होने वाली आय 2024 में 11% की दर से बढ़कर 9,200 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। अनुमान है कि ओटीटी पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री के लिए भुगतान करने वाले उपयोगकताओं की संख्या 9.5 से 11.8 करोड़ के बीच है।

लोक प्रसारक प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के समृद्ध संग्रह, क्षेत्रीय कलाओं, वृत्तचित्रों, शास्त्रीय संगीत, साहित्य-आधारित कार्यक्रमों और बहुभाषी सामग्री को विश्वव्यापी दर्शकों के लिए

सुलभ बनाकर इस पहुंच को और मजबूत किया है।

वेव्स ओटीटी ने उभरते फिल्म निमार्ताओं और रचनाकारों को समर्थन देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। ये उन्हें विविध वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित वितरण मंच प्रदान करता है।

वेव्स ओटीटी मुख्य रूप से एक सदस्यता-मुक्त सार्वजनिक सेवा मंच है और यह सदस्यता-आधारित मॉडल पर काम नहीं करता है। विज्ञापन इसकी आय का मुख्य स्रोत है। इसका उद्देश्य भारत और विश्व स्तर पर सार्वजनिक प्रसारण सामग्री तक सभी की पहुंच को सुलभ बनाना है।

यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में विकास और विस्तार के चरण में है और इसके अंतरराष्ट्रीय उपयोगकताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आय के स्रोत धीरे-धीरे विकसित किए जा रहे हैं।

इसके आरम्भ होने के पहले वर्ष में ही 80 लाख से अधिक डाउनलोड के साथ उपयोगकर्ता वृद्धि में उल्लेखनीय उछाल आया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुभाषी भारतीय सामग्री और सार्वजनिक सेवा मीडिया की बढ़ती मांग को दशार्ता है।

सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 (2023 में संशोधित) जोड़ी गई नई धारा 7(1बी)(ए) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3) के अंतर्गत केंद्र सरकार को चोरी की गई फिल्म सामग्री जारी करने वाले मध्यस्थों पर कार्रवाई करने का अधिकार देती है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज लोकसभा में श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई मादम द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में प्रस्तुत की।

आईएमडी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पूवार्नुमान मॉडल की सटीकता में काफी सुधार हुआ

(जीएनएस)।

आईएमडी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पूवार्नुमान मॉडल की सटीकता में काफी सुधार हुआ है; हालांकि, 100% सटीकता के साथ पूवार्नुमान करना संभव नहीं है। मौसम विज्ञान उप-मंडलों में मॉनसूनी भारी बारिश का 24 घंटे (1 दिन) पहले पता लगाने का स्किल स्कोर 2024 में 85% है। फिलहाल, आईएमडी के भारी बारिश के पूवार्नुमान की सटीकता, जिसे सही चेतावनियों के प्रतिशत के तौर पर मापा जाता है, एक से पांच दिन के लीड टाइम के लिए क्रमशः 85%, 73%, 67%, 63% और 58% है। कुल मिलाकर, 2014 की तुलना में 2023-2024 में देश भर में भारी बारिश की घटनाओं के लिए पूवार्नुमान की सटीकता में करीब 40% का सुधार हुआ है।

आईएमडी भारी बारिश की मात्रा और भारी बारिश होने वाले क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारी बारिश के प्रभाव-आधारित पूवार्नुमान और जोखिम-आधारित पूवार्नुमान और चेतावनी जारी करता है। चेतावनी मौसम विज्ञान उप-मंडल और जिला स्तर पर जारी की जाती है, जो क्रमशः 7 और 5 दिनों तक मान्य होती है। हर तीन घंटे में नाउकास्टिंग

भी होती है, जिसमें भारी बारिश के लिए अगले तीन घंटों की वैधता होती है।

आईएमडी का अत्याधुनिक पूवार्नुमान सिस्टम देश के सभी जिलों में पूरी तरह से काम कर रहा है। हाई-रिजॉल्यूशन मॉडल और GIS सिस्टम देश के सभी जिलों को कवर करते हैं। डॉप्लर मौसम रडार (डीडब्ल्यूआर) नेटवर्क की बात करें तो, अभी पूरे भारत में 47 डीडब्ल्यूआर काम कर रहे हैं, जिससे देश का 87% कुल क्षेत्र रडार कवरेज में आता है। आने वाले सालों में, एमओईएस के मिशन मौसम के अंतर्गत देश के बाकी बचे खाली वाले क्षेत्र को कवर करने, अतिरेकता देने और डीडब्ल्यूआर नेटवर्क में पुराने रडार को बदलने के लिए जरूरत के हिसाब से डीडब्ल्यूआर लगाए जाएंगे। मंत्रालय मौसम के पूवार्नुमान में अधिक सटीकता हासिल करने के लिए अवलोकन क्षमताओं और आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आईएमडी ने देश में अवलोकन, डेटा एक्सचेंज, मॉनिटरिंग और एनालिसिस, पूवार्नुमान और चेतावनी सेवाओं के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है, जिसमें संवेदनशील जिले भी शामिल हैं।

ऐसे हाई-रिजॉल्यूशन मॉडल के लिए गणितीय सहयोग देने और उन्हें सामान्य रूप से त्वरित समय पर चलाने के लिए, कंप्यूटिंग सुविधाओं (अरुणिका और अर्का) को भी बहुत बढ़ाया गया है, जिससे भारी मात्रा में डेटा को एकीकृत किया जा सके और मीसोस्केल, क्षेत्रीय और वैश्विक मॉडल को हाई रिजॉल्यूशन पर चलाया जा सके। इसके साथ ही, हाल ही में, एमओईएस ने भारत को "मौसम के लिए तैयार और क्लाइमेट-स्मार्ट" देश बनाने के लिए एक नई केंद्रीय योजना, "मिशन मौसम" लॉन्च की है। असुरक्षित आबादी तक चेतावनियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हाल ही में लॉन्च की गई भारत पूवार्नुमान प्रणाली (भारतएफएस) मुख्य रूप से कम समय और मध्यम अवधि के मौसम के पूवार्नुमान को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 13 दिसंबर 2025 तक ट्यूनीशिया के ट्यूनिस में आयोजित ' अफ्रीका फूड 2025' में भाग लिया

वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना: खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने ट्यूनिस में आयोजित अफ्रीका फूड 2025 सम्मेलन में उद्योग जगत के दिग्गजों और सरकारी हितधारकों के साथ व्यापार, निवेश और खाद्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्तालाप किया

(जीएनएस)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 13 दिसंबर 2025 तक ट्यूनीशिया के ट्यूनिस में आयोजित ' अफ्रीका फूड 2025' में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप सचिव

श्री विवेक कुमार सिंह और उप सचिव श्री अरुणव सेन गुप्ता ने किया।

इस आयोजन के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया पवेलियन में उद्योग जगत के हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से वार्तालाप करते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने ट्यूनीशिया सरकार के प्रतिनिधियों और विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ भी द्विपक्षीय सहयोग और बाजार पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से बातचीत की।

इस यात्रा के अंतर्गत, प्रतिनिधिमंडल ने ट्यूनिस में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का दौरा किया और बहुमूल्य जानकारी और प्रतिक्रिया साझा की, जिससे खाद्य सुरक्षा बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को मजबूत करने पर चर्चा में योगदान मिला।

यह भागीदारी खाद्य सुरक्षा एवं प्रसंस्करण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, व्यापार संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का समर्थन करने के लिए खाद्य एवं खाद्य प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निरंतर प्रयासों को दशार्ती है।

खाड़ी देशों में विदेशी तैनाती पर भारतीय तटरक्षक बल का जहाज सार्थक एक रणनीतिक यात्रा में ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंचा

(जीएनएस)।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का अपतटीय गश्ती पोत सार्थक ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंच गया है। रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह गहरे पानी का बंदरगाह भारत को ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने वाला एक सीधा व सुरक्षित समुद्री मार्ग उपलब्ध कराता है। यह पोत 16 से 19 दिसंबर, 2025 तक चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ईरान में रहेगा।

चाबहार बंदरगाह पर भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के इस जहाज की यह पहली यात्रा है, जो क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी को स्पष्ट रूप से दशार्ती है। यह दौरा अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सुरक्षित एवं भरोसेमंद आपूर्ति लाइनों को सुदृढ़ करने की भारत की क्षमता को भी रेखांकित करती है।

भारतीय तटरक्षक बल का जहाज सार्थक बंदरगाह पर प्रवास के दौरान ईरानी नौसेना तथा ईरान की अन्य

समुद्री एजेंसियों के साथ विभिन्न पेशेवर एवं सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेगा। इनमें शिष्टाचार भेंट, कार्य संबंधी संवाद व विचार-विमर्श शामिल हैं, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संस्थागत संबंधों को सुदृढ़ करना तथा समुद्री सुरक्षा, सहयोग एवं आपसी समझ को और अधिक गहरा करना है।

बंदरगाह के प्रमुख आकर्षणों में समुद्री खोज एवं बचाव (एसएआर), समुद्री कानून प्रवर्तन (एमएलई) और समुद्री प्रदूषण रोधी कार्रवाई (एमपीआर) पर केंद्रित संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां शामिल होंगी। चाबहार बंदरगाह में तेल रिसाव और खतरनाक तथा हानिकारक पदार्थों (एचएनएस) के रिसाव से निपटने पर आधारित समुद्री प्रदूषण रोधी प्रतिक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे दोनों पक्षों के समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता प्रदर्शित हो सके। इसके अतिरिक्त, एमआरसीसी-से-एमआरसीसी समन्वय अभ्यास, एक टेबल-टॉप अभ्यास तथा संयुक्त दौरा, बोर्डिंग, तलाशी व जब्ती (वीबीएसएस) अभ्यास आयोजित किए जाएंगे, जो दोनों देशों के बीच सहभागिता, आपसी समन्वय एवं परिचालन तत्परता को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

पैशेवर गतिविधियों के अतिरिक्त, इस यात्रा के दौरान खेल प्रतियोगिताओं के अलावा एक बीच वॉकथॉन भी आयोजित किया जाएगा, जिनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेट सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

आस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियां बान्डी बीच पर घटना को लेकर बहुत गंभीर

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को जश्न मना रहे बान्डी बीच पर लोगों पर दो आतंकियों ने हमला कर दिया। इस दौरान 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों से भिड़ गया और कई जानें बचाईं। हुआ यूं कि रविवार को सिडनी के बान्डी बीच पर यहूदियों के हनुक्का पर्व पर लोग पर्व का मजा उठा रहे थे। हनुक्का यहूदियों का सालाना त्यौहार है। इस दौरान दो बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। गोलियों की आवाजें सुनकर बीच पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। इस अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। आतंकियों की निशानदेही हो चुकी है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले बाप और बेटे हैं, जिनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई। आस्ट्रेलिया जांच एजेंसियों ने आरोपी के बैकग्राउंड की जांच शुरू कर दी है। शूटिंग में शामिल पिता (50 वर्षीय) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका 25 वर्षीय बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भती है, सिडनी अटैक में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। आस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियां इस घटना को लेकर बहुत गंभीर है। अहम बात यह भी है कि हमले में शामिल पिता-पुत्र की पहचान पाकिस्तानी मूल के रूप में हुई है। वहीं अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने भी दोनों आतंकियों को पाकिस्तानी नागरिक बताया है। हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और सिडनी में रह रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि गोलीबारी के बाद पास ही एक सड़क पर एक कार से कई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लेसिव डिवाइस यानी विस्फोटक बरामद किए गए, जिससे आशंका है कि हमले की साजिश इससे काफी ज्यादा तबाही पैलाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की थी। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी एसियो ने पुष्टि की है कि हमलावरों में से एक पहले से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में संदिग्ध था, लेकिन उसे तत्काल खतरे के रूप में लिस्ट नहीं किया गया था। इधर दोनों आतंकी गोलियां बरसा रहे थे उधर 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी पर झपट्टा मारा और उससे बंदूक छीन ली, जिससे कई लोगों को सुरक्षित निकालने का मौका मिल गया। लोग अहमद अल अहमद को ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कह रहे हैं। अहमद जब आतंकी साजिद से मुठभेड़ करने जा रहा था, तब उनके भाई ने उन्हें रोका था। तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे वुछ हुआ तो परिवार को बताना कि मैं लोगों की जान बचाते हुए मारा गया। अहमद फल-सब्जी की दुकान चलाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले की निंदा हुई है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से लेकर मुस्लिम-अरब देशों की ओर से भी आतंकवाद और हिंसा के सभी रूपों को खारिज किया है। मगर यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और विरोध के बावजूद किसी समुदाय से नफरत की भावना में डूबे को रोक पाना एक मुश्किल चुनौती है। यह स्वाभाविक है कि इस आतंकी हमले की वैश्विक स्तर पर निंदा होगी और शोक-संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। दुनिया भर में जिहादी आतंक का खतरा जिस तरह उभर रहा है उसका मुकाबला तभी किया जा सकता है जब पूरा विश्व समुदाय मिलकर इस उठते खतरे का ईमानदारी से सामना करे और मिलकर मुकाबला करने के लिए कदम उठाएं। बान्डी बीच के हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। दोनों ही आतंकी पाकिस्तानी मूल के निकले। यह किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान विश्व की सबसे बड़ी आतंकी पैक्ट्री है जहां साल दर साल हजारों आतंकी तैयार किए जाते हैं। भारत तो बार-बार इस बात को कहता रहता है पर दुनिया मानने को तैयार नहीं, पहलगाम हमला भी इसी तरह के आतंकियों ने किया था पर दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। अब तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में यह हमला हुआ है, अब विश्व को इस पर क्या कहना है?

स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए 'सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन' कार्यक्रम में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए के चेक वितरण का गौरवशाली समारोह अहमदाबाद में आयोजित

■ उप मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री और शहरी विकास राज्य मंत्री की उपस्थिति

■ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

● श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने देश के समक्ष यह उदाहरण पेश किया कि दूरदर्शी नेतृत्व और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ यदि धन की कमी न हो, तो शहरी विकास कितनी तेजी से किया जा सकता है

● जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के विरुद्ध राज्य के शहरों ने ग्रीन स्पेस, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छ सर्वेक्षण में लीड ली है

● विकास के कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को वरीयता दें

● 2035 में जब हम गुजरात की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब तक राज्य के शहरों को देश में उत्कृष्ट सुविधा युक्त शहर बनाने का अवसर है

● श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात से जो विकास पथ शुरू किया था, उस पर आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

● सुनिश्चित करें कि सभी विकास कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके पूर्ण हों : शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई

गांधीनगर, 17 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए ह्यसिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनह्ल यानी नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहरी निवेश कार्यक्रम में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे शहरों और महानगरों ने ग्रीन स्पेस, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता सर्वेक्षण में लीड ली है। इतना ही नहीं, सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने के लिए चार ह्यआरह्ल रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल और रिकवर पर फोकस किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में शहरी विकास वर्ष की शुरूआत की थी, यह वह दौर था जब देश में शहरीकरण को एक चुनौती माना जाता था। उन्होंने हमारी विरासत के अनुरूप शहरी विकास मॉडल विकसित करने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की मजबूत नींव रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में शहरी विकास वर्ष के जरिए इसका श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है कि, यदि दूरदर्शी नेतृत्व हो और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ धन की कोई कमी न हो, तो शहरी विकास कितनी तेजी से किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास वर्ष 2005 की दो दशकों की सफलता के चलते मॉडर्न अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी आधुनिक शहरी परिवर्तन में बड़ा बदलाव आया है। इस परिवर्तन को और अधिक गति देने के लिए राज्य सरकार ने सर्वस्पर्शी, सर्वपोषक और सर्वसमावेशी नगरों के विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया है।

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में बुधवार को अहमदाबाद आयोजित कार्यक्रम में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को सर्वांगीण विकास कार्यों के लिए एक साथ, एक ही मंच से कुल 2800 करोड़ रुपए राशि के चेक वितरित किए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई और राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला की उपस्थिति में राज्य की 8 महानगर पालिकाओं को कुल 2132 करोड़ रुपए तथा नवगठित 9 महानगर पालिकाओं को 40-40 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 360 करोड़ रुपए की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए दी। इसके अलावा, राज्य की 152 नगर पालिकाओं को कुल 308 करोड़ रुपए सहित कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ऐसा वित्तीय प्रबंधन किया है, जिसमें नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के आयोजन में धन की कोई कमी रहे। अब नगर पालिकाओं को लोगों के विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन का उपयोग करने की क्षमता बढ़ानी होगी।

उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को वरीयता देने का प्रेरक सुझाव देते हुए कहा कि स्वच्छता सभी का सहज स्वभाव बन गया है, ऐसे में नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं को चाहिए कि वे इस दिशा में और अधिक पहल करने का दायित्व निभाएं।

श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने वाले राज्य के 6 शहरों का उल्लेख किया और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सभी शहरों को लीड लेने और प्रत्येक वार्ड में कचरे का 100 फीसदी पृथक्करण करने के साथ ही नगर पालिकाओं में बिजली बिल की बचत के लिए हरित एवं स्वच्छ सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण का रोडमैप ह्यअर्निंग वेल, लिविंग वेलह्ल के संकल्प के साथ तैयार किया गया है। 2047 के विकसित भारत से पहले, जब 2035 में गुजरात की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, तब तक हमारे शहरों को देश में उत्कृष्ट सुविधा युक्त शहर बनाने का अवसर है।

उन्होंने महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि नागरिक-केंद्रित सेवाओं और मोबाइल गवर्नेंस का दायरा बढ़ाते हुए सभी शहरों में टैक्स कलेक्शन और बिजली बिल सहित सभी बिलों के भुगतान के लिए यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस मौके पर शहरी विकास के लिए एक ही स्थल से राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को चेक वितरित करने के इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं और मुश्किलों के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्व और शहरी विकास के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार प्रयासरत रहते हुए जनकल्याण के अनेक कार्य पूर्ण कराए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के अनेक शहरों ने आगे बढ़कर देश में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दशक पहले की सरकारों के दौर में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में निरंतर मुश्किलों के बीच जीना पड़ता था। लेकिन, श्री नरेन्द्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री शासन की कमान संभालने के बाद गुजरात के शहर और जिले लगातार विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़े हैं और आज पूरा देश विकास की इस तेज गति को देख रहा है।

उन्होंने उच्च स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के साथ नगरों के सतत विकास की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य की 9 नगर पालिकाएं अब महानगर पालिका बन गई हैं। उन्होंने धोलेरा और गिफ्ट सिटी का उदाहरण देते हुए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया।

शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात के विकास के लिए अनेक नए आयाम गढ़े और योजनाएं लागू कीं। उन्होंने ज्योतिग्राम योजना, शाला प्रवेशोत्सव और वाइब्रेंट गुजरात जैसी योजनाओं और अभियानों के अलावा आदिवासी विकास के लिए अलग से बजट आवंटन तथा 2009-10 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की थी।

श्री देसाई ने कहा कि उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी विकास विभाग का बजट 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। शहरों में सड़क, सैनिटेशन, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर सहित शहरी विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए शहरी विकास विभाग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने सभी महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के पदाधिकारियों से सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर बल दिया।

शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने स्वागत भाषण में कहा कि राज्य सरकार महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सदैव कटिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास की लगातार चिंता की थी। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी शहरी विकास विभाग के बजट में लगातार बढ़ोतरी कर लोगों की सुख-सुविधा बढ़ाने और अनेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।

इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की झलक दिखाने वाली लघु फिल्म भी दिखाई गई।

कार्यक्रम में विधानसभा के उप मुख्य सचेतक श्री जगदीशभाई मकवाणा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, स्थानीय विधायक, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन, कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज श्रीमती रेम्या मोहन, म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की अपर आयुक्त श्रीमती वीमा पटेल सहित राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

पिछले 5 वर्षों के दौरान इसरो द्वारा कुल 22 उपग्रह प्रक्षेपित

(जीएनएस)।

इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन

पिछले 5 वर्षों (दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025) के दौरान इसरो द्वारा कुल 22 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। इनमें से 7 पृथ्वी अवलोकन, 4 संचार, 2 नेविगेशन, 3 अंतरिक्ष विज्ञान तथा 6 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन से संबंधित हैं। प्रक्षेपणों का विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 उपग्रह परियोजनाओं में किसी प्रकार की लागत वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि, चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 उपग्रहों के लिए क्रमशः 28 माह और 46 माह की समय-वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

आदित्य-एल1: परियोजना में समय-वृद्धि का कारण कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, कक्षा को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) से लैग्रेंजियन बिंदु (L1) में बदलना रहा, जिसके चलते उपग्रह के विन्यास में बदलाव करना पड़ा। इसके अलावा, पेलोड के विकास में अधिक समय लगना तथा दीर्घ-अवधि वाले उपकरणों/सामग्रियों की खरीद में लगने वाला अतिरिक्त समय भी समय-वृद्धि के प्रमुख कारण रहे।

चंद्रयान-3: परियोजना में समय-वृद्धि चंद्रयान-2 विफलता विश्लेषण समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों को शामिल करने के लिए प्रणालियों के पुनः विन्यास, कोविड-19 महामारी, नए विशेष परीक्षणों के संचालन तथा नए सेंसर के विकास के कारण हुई।

गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) तक स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 में आधिकारिक स्वीकृति दी गई थी। इसके अंतर्गत समान विन्यास में दो मानव रहित मिशन और एक मानव सहित मिशन संचालित किए जाने का प्रावधान था। इस कार्यक्रम के लिए कुल ₹9,023 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी गई थी तथा मानव सहित मिशन के प्रक्षेपण का लक्ष्य मई 2022 निर्धारित किया गया था।

हाल ही में अक्टूबर 2024 में गगनयान कार्यक्रम के दायरे में संशोधन किया गया, जिसके तहत मिशनों की

संख्या तीन से बढ़ाकर आठ कर दी गई। इसमें एक अतिरिक्त मानव रहित मिशन (G1) तथा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के लिए चार अग्रदूत (प्रीकर्सर) मिशन शामिल किए गए हैं। संशोधित कार्यक्रम के लिए कुल बजट प्रावधान ₹20,193 करोड़ किया गया है। संशोधित स्वीकृति के अनुसार सभी गतिविधियां प्रगति पर हैं और पहले मानव सहित मिशन का लक्ष्य वर्ष 2027झ28 रखा गया है।

गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो नियोजित मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विभिन्न प्रणालियों का विकास और निर्माण कर रहा है। मानव उड़ान के लिए निर्धारित कड़े ह्यूमन रेटिंग मानकों को ध्यान में रखते हुए, मानव-रेटेड प्रक्षेपण यान (HLVM3) की संरचनाओं, सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम, क्रू मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम तथा पैराशूट आधारित अवरोह/धीमी गति प्रणाली के व्यापक परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। इसके अलावा, अत्यंत महत्वपूर्ण क्रू एस्केप सिस्टम के मोटरों का भी विकास कर लिया गया है और उनके स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। साथ ही, स्वदेशी पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली के विकास का कार्य समानांतर रूप से प्रगति पर है।

प्रमुख अवसंरचनाएं जैसे ऑर्बिटल मॉड्यूल प्रिपरेशन फैसिलिटी, गगनयान कंट्रोल सेंटर तथा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की जा चुकी हैं। दूसरे लॉन्च पैड में आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए हैं। टीवी-डी1 (TV-D1) और आईएडीटी-01 (IADT-01) जैसे अग्रदूत (प्रीकर्सर) मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। ग्राउंड ट्रैकिंग नेटवर्क, स्थलीय संचार लिंक तथा आईडीआरएसएस-1 (IDRSS-1) फीडर स्टेशनों की स्थापना कर ली गई है। क्रू मॉड्यूल रिकवरी योजना तथा इसके लिए तैनात किए जाने वाले संसाधनों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले मानव रहित मिशन (G1) के लिए HLVM3 के सभी चरण और क्रू एस्केप सिस्टम (CES) मोटर तैयार हैं। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल की प्रणालियाँ विकसित कर ली गई हैं तथा उनके संयोजन और एकीकरण (असेंबली एवं इंटीग्रेशन) का कार्य अंतिम चरण में है। पहला मानव सहित मिशन वर्ष 2027-28 में लक्षित है।

भारत ने वर्तमान में संचालित पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम-3 प्रक्षेपण यानों के माध्यम से निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में 10 टन तक तथा भू-समकालिक ट्रांसफर कक्षा (GTO) में 4.2 टन तक के उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इन प्रक्षेपण यानों ने पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन और अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े उपग्रहों के लिए स्वतंत्र अंतरिक्ष पहुँच सुनिश्चित की है। विस्तारित अंतरिक्ष दृष्टि को पूरा करने हेतु प्रक्षेपण यान क्षमताओं को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) के विकास को मंजूरी दी है, जो निम्न पृथ्वी कक्षा में 30 टन तक की अधिकतम पेलोड क्षमता प्रदान करेगा। अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकियों का भी विकास किया जा रहा है, जिसमें आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य NGLV शामिल है, जिसकी LEO में 14 टन पेलोड क्षमता होगी। इसके अतिरिक्त, एक पंखयुक्त बॉडी अपर स्टेज का भी विकास किया जा रहा है, जो कक्षा से पृथ्वी पर वापस लौटेगा और स्वचालित रूप से रनवे पर उतरने में सक्षम होगा।

अधिक शक्तिशाली और अधिक दक्ष प्रोपल्शन प्रणालियों के विकास के संबंध में, इसरो ने एलवीएम-3 प्रक्षेपण यान में शामिल किए जाने हेतु उच्च-थ्रस्ट (2000 'ठ) अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन के विकास का कार्य शुरू किया है। इसके साथ ही, नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) के लिए उच्च-थ्रस्ट इंजन हेतु एक पर्यावरण-अनुकूल मीथेन आधारित प्रोपल्शन प्रणाली की भी परिकल्पना की जा रही है, जिससे प्रस्तावित मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए प्रक्षेपण यान की प्रौद्योगिकीय तत्परता सुनिश्चित की जा सके। इनके अतिरिक्त, ड्यूल-फ्यूल स्क्रैमजेट इंजन की दिशा में एक एयर-ब्रीदिंग प्रोपल्शन प्रणाली का विकास भी प्रगति पर है।

सरकार ने अंतरिक्ष विभाग की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। सरकार की स्पेस विजन 2047 के अंतर्गत वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना तथा वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है।

डब्लूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में विशेषज्ञों ने अश्वगंधा के भविष्य की रूपरेखा तैयार की

(जीएनएस)।

आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण रसायन जड़ी बूटियों में से एक अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा) ने दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन, 2025 में आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना, जिसने साक्ष्य-आधारित वैश्विक संवाद के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व की पुष्टि की।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (डब्ल्यूएचओ-जीटीएमसी) द्वारा 'अश्वगंधाः पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक प्रभाव तक - अग्रणी वैश्विक विशेषज्ञों का दृष्टिकोण' शीर्षक से एक सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने प्रमुख वैश्विक विशेषज्ञों, नियामकों, शोधकर्ताओं एवं नीति निमार्ताओं को अश्वगंधा के आसपास विकसित हो रहे वैज्ञानिक, नियामकीय और सुरक्षा परिदृश्य पर विचार-विमर्श के लिए एकत्रित किया।

अश्वगंधा अपनी अनुकूलनीय, स्नायु सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा गुणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर मान्यता प्राप्त कर रहा है। इस पर हुई चर्चा ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों एवं समकालीन वैज्ञानिक सत्यापन के बीच के पुल को मजबूती प्रदान की। विशेषज्ञों ने इसके समर्थन के लिए कठोर पूर्व-नैदानिक एवं नैदानिक अनुसंधान, सुरक्षा मूल्यांकन, औषधि सतर्कता एवं मानकीकरण के महत्व पर बल दिया।

इस सत्र का संचालन विश्व अश्वगंधा परिषद के सचिव डॉ. जे.बी. गुप्ता ने किया जिसमें अग्रणी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने मुख्य प्रस्तुतियां दी। अमेरिकन हर्बल फामाकोपिया के डॉ. रॉय अप्टन ने पहचान, गुणवत्ता परीक्षण एवं चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए वैश्विक मानकों पर प्रकाश डाला। सुश्री मारी ल्यरा, खाद्य एवं पशु आहार विभाग की प्रमुख, मेडफाइल्स लिमिटेड, फिनलैंड ने यूरोप के नियामक परिवेश और अश्वगंधा की बढ़ती स्वीकार्यता पर अपने विचारों को साझा किया। डॉ. इखलास खान, निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान केंद्र, मिसिसिपी विश्वविद्यालय ने नियामक निर्णय लेने हेतु कार्यप्रणाली की सटीकता एवं ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता पर बल दिया। डब्ल्यूएचओ-जीटीएमसी की डॉ. गीता कृष्णन ने अश्वगंधा को वैश्विक स्तर पर अपनाने में वादे एवं सतर्कता के बीच संतुलन पर प्रकाश डाला।

एक संवादात्मक पैनल चर्चा में विशेषज्ञों के बीच मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, प्रभावकारिता की पुनरावृत्ति सुनिश्चित करने एवं साक्ष्य-आधारित अश्वगंधा सूत्रीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर खुलकर विचार-विमर्श हुआ। सत्र का समापन पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए अश्वगंधा को पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल संरचना में स्थापित करने के लिए निरंतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर आम सहमति के साथ हुआ।

विचार-विमर्श में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप, सुरक्षित, वैज्ञानिक एवं चिरस्थायी उपायों से पारंपरिक चिकित्सा को समकालीन स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने की बढ़ती वैश्विक प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई।

विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन पारंपरिक, पूरक एवं एकीकृत चिकित्सा पर संवाद, सहयोग और नीतिगत संरेखण के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें साक्ष्य, सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

शिक्षक के हमले व पुलिस की प्रताड़ना से पीड़ित परिवार ने भाकियू (भानु) की ली शरण न्याय दिलाने की लगाई गुहार

(जीएनएस)।

पीलीभीत बिलसंडा थाना क्षेत्र का एक चर्चित मामला सामने आया है वहीं के स्थानीय विद्यालय के शिक्षक के हमले और पुलिस की प्रताड़ना से पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार सहित भारतीय किसान यूनियन (भानु) की शरण में पहुंचा। पीड़ित ने संगठन के पदाधिकारियों के समक्ष पूरे मामले की सच्चाई रखकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई।पीड़ित की आप बीती को गंभीरता से लेते हुए भाकियू (भानु) के तहसील अध्यक्ष ने मामले का संज्ञान लिया और पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच व दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की

मांग की। भाकियू भानु तहसील अध्यक्ष का कहना है कि यदि मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई तो बिलसंडा पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

भाकियू (भानु) के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इससे पूर्व भी बिलसंडा पुलिस द्वारा कई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को दबाए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। भाकियू भानु तहसील अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस प्रशासन ने इस प्रकरण में न्यायोचित कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन के दौरान ऐसे मामलों का खुलासा किया जाएगा।

संगठन ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की है।

पीलीभीत-पूरनपुर मार्ग पर रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकराई: कोहरे के कारण हादसा

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पीलीभीत-पूरनपुर मार्ग पर मंगलवार-बुधवार की मध्य रात्रि को घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकरा गई। थाना गजरौला क्षेत्र के पिपरिया मोड़ के पास हुई इस दुर्घटना में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, और चालक समेत दो यात्री घायल हो गए। हादसे के समय बस लखनऊ से यात्रियों को लेकर पीलीभीत आ रही थी।

घटना तड़के करीब 3:30 बजे घटी, जब पीलीभीत डिपो की बस (वढ 78 छठ 0362) पिपरिया मोड़ के पास सीमेंट ईंट प्लांट के निकट खड़े गन्ने लदे ट्रक (वढ 22 ळ 5131) से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घना कोहरा होने से दृश्यता कम थी, जिस कारण चालक ट्रक को देख नहीं पाया। बस में 7-8 यात्री सवार थे, जिनमें चालक दयाराम (40 वर्ष, ग्राम चिरौरा, बरखेड़ा) के सिर पर चोटें आईं, जबकि यात्री आयुष शर्मा (आवास विकास कॉलोनी, पीलीभीत) भी घायल हुए।

सूचना पर थाना गजरौला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल ले जाकर उपचार कराया। अन्य यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बस से गंतव्य भेजा गया। थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह ने बताया कि हादसा कम दृश्यता व खराब ट्रक के कारण हुआ, और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया।

कोहरे के मौसम में सतर्कता बरतने की अपील करते हुए पुलिस ने चेतावनी दी कि रात के समय धीमी गति से वाहन चलाएं।

बी-पैक्स बमरौली केंद्र पर धान तौल में धांधली

(जीएनएस)।

पीलीभीत,बीसलपुर क्षेत्र के बी-पैक्स बमरौली केंद्र पर धान तौल में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लग रहा है, जहां किसानों को ठगने का खेल चल रहा। केंद्र प्रभारी सत्यम शुक्ला पर भौतिक तौल न कराकर पूरे दिन केवल अंगूठे लगवाने, टोकन काटने में अनियमितता करने और पसंदीदा किसानों को ही फ्ऋ टोकन देने का गंभीर आरोप है। मंडी सचिव की कथित मिलीभगत से यह धंधा फल-फूल रहा, जिससे किसानों में भारी आक्रोश फैल गया।

किसानों के अनुसार, ट्रॉलियां एक-एक सप्ताह तक खड़ी रखकर टालमटोल की जाती है, और तौल के नाम पर वजन कम बताकर भुगतान घटाया जाता। एक किसान ने बताया, "भौतिक तौल की बजाय सिर्फ हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो रहा। पसंदीदा लोगों को ही टोकन मिलते हैं, बाकियों को घुमाया जाता।" बीसलपुर मंडी का यह पूरा मामला किसानों को गुमराह करने का उदाहरण बन गया, जहां धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी साफ दिख रही।

स्थानीय किसान संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि उच्चाधिकारियों से जांच कराई जाए। प्रशासन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी कि यदि धांधली न रुकी तो आंदोलन की राह अपनाएंगे।

कड़ाके की ठंड से जनता त्रस्त: अलाव की व्यवस्था नदारद, नगर पालिका की लापरवाही पर सवाल

(जीएनएस)।

पीलीभीत,विकासखंड पूरनपुर में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है, लेकिन नगर पालिका की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था न होने से गरीब, मजदूर व राहगीर ठिठुरने को मजबूर हैं। आधा दिसंबर बीत जाने के बावजूद चौक-चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर अलाव पूरी तरह गायब हैं, जिससे रात के समय ठंड का प्रकोप और बढ़ गया।

बुजुर्ग, बच्चे व असहाय लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे, जहां ठंड से बचाव के दावे केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर पालिका की सुस्ती व जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता से आमजन में भारी नाराजगी फैल गई। एक राहगीर ने बताया, "ठंड इतनी तेज है कि रात में बाहर निकलना मुश्किल, लेकिन अलाव न होने से मजबूरन सड़कों पर ही काटनी पड़ रही।"

लोगों ने नगर प्रशासन से तत्काल अलाव लगवाने की मांग उठाई, ताकि सर्दी के इस मौसम में राहत मिल सके। नगर पालिका ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सवाल उठ रहा कि आखिर कब जागेगा प्रशासन। ठंड से बचाव के उपायों में तेजी लाने की जरूरत है।

66 गौशालाएं होने के बाद भी सड़कों पर छुट्टा पशुओं का आतंक, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी

(जीएनएस)।

पीलीभीत,जिले में छोटी-बड़ी मिलाकर 66 गौशालाएं होने के बावजूद सड़कों पर छुट्टा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और सरकारी दावों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। आवारा मवेशियों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है।

जानकारी के अनुसार, जिले की इन 66 गौशालाओं में अभी भी पशुओं को रखने की पर्याप्त जगह उपलब्ध है, फिर भी आवारा पशु मुख्य बाजारों, हाईवे और गांवों की सड़कों पर खुलेआम घूमते देखे जा रहे हैं। इससे न केवल आवागमन बाधित होता है, बल्कि दोपहिया चालकों और राहगीरों के लिए गंभीर

खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम और रात के समय सड़कों पर सबसे ज्यादा जोखिम रहता है।

अधिकारियों का दावा है कि छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान बीच-बीच में चलाया जाता है, लेकिन फिलहाल यह अभियान पूरी तरह ठप पड़ा है। शहर और ग्रामीण इलाकों में हालात यह हैं कि लोग खुद ही इन पशुओं को हांककर हटाने को मजबूर हैं। नागरिकों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और सरकार की मंशा के विपरीत जमीनी स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से नियमित पकड़ अभियान चलाए, गौशालाओं की क्षमता का पूरा उपयोग करे और हादसों की रोकथाम के लिए जवाबदेही तय करे। लोगों का सवाल है कि जब गौशालाओं में जगह मौजूद है, तो छुट्टा पशु सड़कों पर क्यों छोड़े जा रहे हैं?

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मातृ सम्मेलन: महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा पर दिया संदेश।

(जीएनएस)।

पीलीभीत पूरनपुर। पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर माती में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सप्तशक्ति संगम/मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां महिला सशक्तिकरण, सम्मान व सुरक्षा पर महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, और वक्ताओं ने नारी को समाज की आधारशिला बताते हुए स्वावलंबन व जागरूकता पर बल दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख पूरनपुर मानसी सिंह ने की, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा व एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य वक्ता संजीता सिंह (आरएसआरडी) ने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला, जबकि मुख्य अतिथि किरन देवी (प्रधानाचार्य, कंपोजिट विद्यालय मुरादपुर) ने सामाजिक एकता व सुरक्षा उपायों पर चर्चा की। विशिष्ट अतिथि सपना पाल (उत्तर प्रदेश पुलिस, थाना सेहरामऊ) ने महिलाओं की सुरक्षा योजनाओं, हेल्पलाइन व कानूनी अधिकारों की जानकारी साझा की।

शिविर में महिलाओं को प्रेरित करने वाले सत्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई, और ग्रामीण महिलाओं ने अपनी समस्याओं पर चर्चा की। कार्यक्रम का समापन नारी सम्मान व सशक्तिकरण के संकल्प के साथ हुआ, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक संदेश फैला।

यह कार्यक्रम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मुरादपुर माती में आयोजित किया गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य संजीव बाजपेई ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया।

रिक्रूट आरक्षियों के लिए विशेष योग सत्र: एसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में फिटनेस एक्सपर्ट ने कराया अभ्यास

(जीएनएस)।

पीलीभीत।पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देशन में जिले में रिक्रूट आरक्षियों के लिए विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया, जहां फिटनेस एक्सपर्ट कुलविंदर सिंह ने योगासनों, प्राणायाम व संतुलन अभ्यास कराया। सत्र में मानसिक एकाग्रता व तनाव प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया, और पुलिस सेवा में योग को आवश्यक बताते हुए इसके शारीरिक व मानसिक लाभों पर चर्चा की गई।

कुलविंदर सिंह ने आरक्षियों को विभिन्न आसनों के माध्यम से शारीरिक लचीलापन, सांस नियंत्रण व संतुलन सुधारने के तरीके सिखाए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए योग तनाव मुक्ति व एकाग्रता बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है, जो कर्तव्य पालन में सहायक सिद्ध होता है। सत्र में अरढ विक्रम दहिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने आरक्षियों का उत्साह बढ़ाया।

यह आयोजन पुलिस विभाग में फिटनेस को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, और एसपी ने भविष्य में ऐसे सत्रों को नियमित करने का संकेत दिया। आरक्षियों ने योगाभ्यास को उपयोगी बताते हुए सराहना की।

गन्ना क्रय केंद्र-34 पर ट्रांसपोर्टरों की मनमानी: किसानों का आर्थिक शोषण जारी

(जीएनएस)।

पीलीभीत,जहानाबाद गन्ना क्रय केंद्र-34 पर ट्रांसपोर्टरों की मनमानी ने किसानों को परेशान कर दिया है, जहां आर्थिक शोषण का सिलसिला थम नहीं रहा। आरोप है कि ट्रांसपोर्टर गन्ना सेंट्रो पर किसानों से तय भाड़े से अधिक राशि वसूल रहे, और भुगतान में देरी कर रहे। इससे किसानों को नुकसान हो रहा, और केंद्र प्रबंधन पर मिलीभगत का शक गहरा गया।

किसानों के अनुसार, ट्रांसपोर्टर ट्रॉलियों के वजन व दूरी के नाम पर अतिरिक्त भाड़ा ऐंठ रहे, जिससे कई किसान मजबूरन अपना गन्ना बेचने में हिचक रहे। एक किसान ने बताया, "केंद्र तक गन्ना पहुंचाने के लिए दोगुना भाड़ा मांगते हैं, और भुगतान भी महीनों बाद मिलता।" यह शोषण गन्ना सत्र के बीच में किसानों की कमर तोड़ रहा, जबकि केंद्र पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुचारू होने का दावा किया जाता है।

किसान संगठनों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल जांच कर ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई करे। केंद्र प्रबंधन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी कि यदि मनमानी न रुकी तो धरना देने को मजबूर होंगे।

भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की प्रेस वार्ता

भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण: व्यापक उपलब्धियाँ और पहलें

(2014झ्रदिसंबर, 2025)

(जीएनएस)।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से दिसंबर, 2025 के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक प्रस्तुति की दिशा में व्यापक एवं बहुआयामी पहलें की हैं। इन प्रयासों ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ किया है।

उन्होंने बताया कि इन पहलों के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार, आधुनिक अवसंरचना का विकास, प्राचीन पांडुलिपियों एवं कलाकृतियों का डिजिटलीकरण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक सहयोग को सशक्त करना तथा भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करना प्रमुख रूप से शामिल रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने प्रेस को बताया कि इस अवधि में देश के प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी; उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना; असम का माँ कामाख्या मंदिर; उत्तर प्रदेश में

श्रीराम मंदिर, अयोध्या; उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर; गुजरात में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण तथा सोमनाथ क्षेत्र में संग्रहालय एवं विरासत विकास शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है।

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि तीर्थ स्थलों तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चार धाम राजमार्ग परियोजना, हेमकुंड साहिब रोपवे, बौद्ध सर्किट विकास तथा करतारपुर साहिब कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया है, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा प्राप्त हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि विरासत आधारित विकास को गति देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना (तीर्थयात्रा पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान) लागू की गई है, जिसके अंतर्गत चिन्हित धार्मिक एवं विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 54 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

इसके साथ ही स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विषयगत पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए 5,290.30 करोड़ रुपये की लागत से 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि ल्फ्क्रऊअ योजना (राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना), जिसे 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया, का उद्देश्य शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और धरोहर संरक्षण को एक समावेशी ढांचे में एकीकृत करना है।

केंद्रीय मंत्री ने प्रेस को अवगत कराया कि इन पहलों के सकारात्मक प्रभाव के रूप में पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जून 2025 तक भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या 16.5 लाख रही, जबकि भारत से बाहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या 84.4 लाख रही। इस गतिविधि से 51,532 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय हुई। उन्होंने बताया कि भारत के आव्रजन ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 में 95.2 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए, जो वर्ष 2022 की तुलना में 47.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1976 से अब तक विभिन्न देशों से कुल 655 प्राचीन वस्तुएँ सफलतापूर्वक भारत लाई गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (अरक) ने 1976 से 2023 के बीच विदेशी देशों से 357 प्राचीन वस्तुएं प्राप्त की हैं, जिनमें से 344 वस्तुएं वर्ष 2014 के बाद प्राप्त की गई हैं।

डॉ. कुमार ने बताया कि राष्ट्र निमार्ताओं और राष्ट्रीय स्मृति को सम्मान देने के उद्देश्य से कई प्रतिष्ठित स्मारकों और संस्थानों का विकास किया गया है, जिनमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया; इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक; डॉ. भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ; कोचरब आश्रम, साबरमती; प्रधानमंत्री संग्रहालय; राष्ट्रीय युद्ध स्मारक; राष्ट्रीय पुलिस स्मारक; जलियांवाला बाग स्मारक; आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय; भारत मंडपम तथा नया संसद भवन शामिल हैं।